



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203]

नई दिल्ली, मंगलवार, 28, 2015/श्रावण 6, 1937

No. 203]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2015/SHRAVANA 6, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली 27 जुलाई, 2015

(निर्णायक समीक्षा)

**विषय :** चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पीवीसी फ्लेक्स फिल्म के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत।

**फा. सं. 15/13/2015 –डीजीएडी .—**वर्ष 1995 और तत्पश्चात यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित “पीवीसी फ्लेक्स फिल्म” (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी।

- यतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल रूप से दिनांक 1 फरवरी 2010 को चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटन से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत की थी। प्राधिकारी ने दिनांक 22 जून 2010 की अधिसूचना सं.



14/4/2010-डीजीएडी के जरिए अनंतिम पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय ने दिनांक 30 जुलाई 2010 की अधिसूचना सं. 79/2010- सीमाशुल्क के जरिए संबद्ध वस्तु पर अनंतिम शुल्क लगाया था। तत्पश्चात, प्राधिकारी ने दिनांक 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना सं. 14/4/2010- डीजीएडी के जरिए निश्चयात्मक शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 25 अगस्त 2011 की अधिसूचना सं. 82/2011 के जरिए चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

3. यतः, मै. पायोनियर पॉलिलेदर्स लि. और मै. एसआरएफ लि. (जिन्हें एतदपश्चात 'याचिकाकर्ता' भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. से पीवीसी फ्लेक्स के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने हेतु याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में पर्याप्त सूचना प्रदान की है। याचिका में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने हेतु प्रथमदृष्टया साक्ष्य निहित हैं।

### शामिल देश

4. इस जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है।

### विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. वर्तमान याचिका पूर्व में अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा के लिए है। दिनांक 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना सं. 14/4/2010- डीजीएडी के जरिए जारी मूल जांच के पूर्ववर्ती अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नोट किया था कि:

“विचाराधीन उत्पाद 'पीवीसी फ्लेक्स फिल्म' है। पीवीसी फ्लेक्स फिल्मों को पीवीसी फ्लेक्स बैनर्स, विज्ञापन साइनेज, बिलबोर्ड्स के लिए पीवीसी फ्लेक्स शीटों और पीवीसी फ्लेक्स टारपॉलिन्स आदि नामों से भी जाना जाता है (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है)। तथापि, पीवीसी फिल्म्स, पीवीसी रिजिड फिल्म्स, कॉटन/कैनवस टारपॉलिन्स, सेल्फ एड्हेसिव विनाइल, वन वे विजन फिल्म/परफोरेटेड विंडो फिल्म और मेश बैनर/फैब्रिक विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं हैं और इसलिए वे इस जांच के दायरे से बाहर हैं।

पीवीसी फ्लेक्स फिल्मों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 39 के तहत टैरिफ शीर्ष सं. 3920 और 3921 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामग्री का आयात और निकासी कई अन्य सीमाशुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत भी की जा रही है जिसमें 39201019, 39201012, 39204900, 39219026, 39219029, 39269099, 39199090, 39181090, 39189090, और 39269080 शामिल हैं। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।”

प्रस्तावित जांच के मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा जांच होने के कारण प्रस्तावित जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो पूर्व में अधिसूचित अंतिम जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद का दायरा था।

### समान उत्पाद

6. याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों उत्पादों में वास्तविक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तु के टैरिफ



वर्गीकरण आदि जैसे मापदंडों के रूप में तुलनीय विशेषताएं हैं। दायर की गई याचिका लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा की समीक्षा, उसे जारी रखने एवं उसमें वृद्धि किए जाने के लिए है और समान वस्तुओं के मुद्दों पर मूल जांच में पहले ही विचार कर लिया गया है। साथ ही प्राधिकारी ने मूल जांच में पहले ही माना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषयगत समान संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु है।

### घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह याचिका मै. पायोनियर पॉलिलेदर्स लि. और मै. एसआरएफ लि. ने दायर की है। कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ताओं का हिस्सा 47.40% है। संबद्ध वस्तु के 8 अन्य उत्पादक हैं, नामतः मै. सनलेक्स फैब्रिक्स प्रा. लि., वेरमोरा फ्लेक्स, क्यूरेक्स फ्लेक्स प्रा. लि., स्वरूप फ्लेक्स, कनैडियन विनाइल, खुशबू पीवीसी फ्लेक्स, जिंदल स्पेशियलिटी टेक्सटाइल्स लि. और नवरत्न स्पेशियलिटी केमिकल्स एलएलपी। सनलेक्स फैब्रिक्स प्रा. लि., क्यूरेक्स फ्लेक्स प्रा. लि., कनैडियन विनाइल, जिंदल स्पेशियलिटी टेक्सटाइल्स लि. और नवरत्न स्पेशियलिटी केमिकल्स एलएलपी ने याचिका का समर्थन किया है। समर्थकों के साथ याचिकाकर्ताओं का कुल भारतीय उत्पादन में 98% हिस्सा बनता है। यह देखा गया है कि पाटनरोधी नियमों के अनुसार उत्पादन में याचिकाकर्ता का “प्रमुख हिस्सा” बनता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता पात्रता संबंधी अपेक्षा को पूरा करते हैं और पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर वे “घरेलू उद्योग” हैं।

### निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

8. यतः विधिवत प्रमाणित प्रस्तुत आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी यह जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है, एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं।

### जांच अवधि

9. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) अप्रैल 2014 – मार्च 2015 (12 माह) की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2011- मार्च 2012, अप्रैल 2012- मार्च 2013, अप्रैल 2013- मार्च 2014 तथा जांच अवधि शामिल हैं। पाटन और क्षति की संभावना की जांच करने के लिए जांच अवधि से इतर जानकारी की भी जांच की जा सकती है।

### प्रक्रिया

10. वर्तमान समीक्षा जांच में दिनांक 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना सं. 14/4/2010-डीजीएडी के जरिए प्रकाशित मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं।
11. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 एवं 20 के उपबंध यथोचित परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे।

### सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत



करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:

**भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,  
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001**

13. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय अंश उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

**समय सीमा**

14. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस पत्र को जारी किए जाने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजा जाना चाहिए। कोई अन्य हितबद्ध पक्ष जिसका पता उपलब्ध नहीं है, वह भी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर टिप्पणियां/सूचना प्रस्तुत कर सकता है।

**गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

15. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अभ्यावेदन के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों में प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा- (क) गोपनीय के रूप में अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख) अगोपनीय के रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)। समस्त प्रस्तुत सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर सबसे ऊपर “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए और सूचना के साथ उसकी सॉफ्ट प्रति होनी चाहिए।
16. गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय एवं अगोपनीय पाठ की दो-दो प्रतियां प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
17. गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है अथवा उसका सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है।
18. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तब प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।



19. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
20. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार पर उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

### सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

### असहयोग

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे .के . दादू ,निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2015

(Sunset Review)

### Initiation of Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on imports of PVC Flex Film, originating in or exported from China PR.

**F. No. 15/13/2015-DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter also referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of “PVC Flex Film” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country).

2. Whereas, The Designated Authority had originally initiated investigations on dumping of subject goods from China PR on 1st February, 2010. The Authority recommended imposition of provisional anti dumping duties vide



notification No. 14/4/2010 - DGAD dated 22nd June, 2010 and Ministry of Finance imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods vide notification No. 79/2010-Customs, dated the 30th July, 2010. The Designated Authority thereafter recommended imposition of definitive duty vide Notification No.14/4/2010-DGAD dated 29th July 2011. Ministry of Finance, vide Notification No. 82/2011 dated 25th August 2011 imposed definitive anti dumping on all imports of subject goods originating in or exported from China PR.

3. Whereas, M/s Pioneer Polyleathers Ltd and M/s SRF Ltd (hereinafter referred to as 'petitioners') have filed a petition for continuation of Anti-dumping duty on imports of PVC Flex from China PR. The petitioners have provided relevant information in the application. The petition contains prima facie evidence for extension of anti-dumping duty on the subject goods from subject country.

### **Country involved**

4 The country involved in this investigation is China PR.

### **Product under consideration and Like Article**

5 The present petition is for sunset review of the anti dumping duty earlier imposed. In the earlier Final Findings of the original investigation issued vide notification No. 14/4/2010-DGAD dated 29th July 2011 the Designated Authority had noted that:

*"The product under consideration is 'PVC Flex Film'. PVC Flex Films are also known as PVC Flex Banners, PVC Flex Sheets for advertising signage, billboards and PVC Flex Tarpaulins, etc., (hereinafter referred to as subject goods). However, PVC Films, PVC Rigid Films, Cotton/Canvas Tarpaulins, Self Adhesive Vinyl, One way vision film/Perforated window film and Mesh Banner/Fabric do not constitute PUC and therefore are outside the purview of this investigation. PVC Flex Films are classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975, under Tariff Heading Nos. 3920 and 3921. The Authority notes that the material is being imported and cleared under a large number of other customs classifications as well, which includes 39201019, 39201012, 39204900, 39219026, 39219029, 39269099, 39199090, 39181090, 39189090, and 39269080. The customs classifications are however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation".*

Proposed investigations being review of existing anti dumping duty, the scope of the product under consideration in the proposed investigation shall remain the same as the scope of the product under consideration in the final findings earlier notified.

### **Like Article**

6 Petitioners have submitted that there is no known difference in subject goods exported from subject country and that produced by the Indian industry. Both the products have comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification, etc. The petition filed is for the review, continuation and enhancement of the quantum of anti dumping duty in force, and the issue of like article has already been dealt with in the original investigation. Further, the Authority has already held in the original investigation that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the subject goods imported from the subject country.

### **Domestic Industry & Standing**

7 The petition has been filed by M/s. Pioneer Polyleathers Ltd and M/s SRF Ltd. Petitioners share in total Indian production is 47.40%. There are eight other producers of the subject goods, namely M/s Sunlex Fabrics Pvt. Ltd., Vermora Flex, Qrex Flex Pvt Ltd, Swaroop Flex, Canadian Vinyl, Khushboo PVC Flex, Jindal Speciality Textiles Ltd



and Navratan Speciality Chemicals LLP. Sunlex Fabrics Pvt. Ltd., Qrex Flex Pvt Ltd, Canadian Vinyl, Jindal Speciality Textiles Ltd and Navratan Speciality Chemicals LLP have supported the petition. Petitioners along with supporters account for 98% share of Indian production. It is seen that production of the petitioners constitutes a “major proportion” in terms of AD Rules. In view of the above, it is seen that the petitioners satisfies the standing and constitutes "Domestic Industry" within the meaning of the Anti Dumping Rules.

#### **Initiation of Sunset Review**

8 WHEREAS, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

#### **Period of Investigation**

9 The period of investigation (POI) is April 2014 – March 2015 (12 months) for the purpose of present investigation. The injury investigation period will however cover the periods April 2011 - March 2012, April 2012-March 2013, April 2013-March 2014 and the POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

#### **Procedure**

10 The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No. 14/4/2010-DGAD dated 29<sup>th</sup> July, 2011 (final findings of the original investigation).

11 The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

#### **Submission of Information**

12 The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**Government of India**  
**Ministry of Commerce and Industry**  
**Department of Commerce**  
**Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties**  
**4th Floor, Jeevan Tara Building**  
**5, Parliament Street, New Delhi – 110001**

13. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

#### **Time Limit**

14. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of issuance of such letter. Any other interested party, whose address is not available, may also submit comments/ information within 40 days from date of publication of this notification.



**Submission of information on confidential basis**

15. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page and accompanied with soft copies.

16. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

17. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

19. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

20. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of public file**

21. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

22. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. K. DADOO, Designated Authority